वन उत्पादकता संस्थान, रांची

दिनांक : 05.11.2020

वन उत्पादकता संस्थान रांची मे REDD+ के लिए **Safeguards Information System** पर आभासीय माध्यम द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। संस्थान के निदेशक डॉ. नितिन कुलकर्णी ने अपने स्वागत उद्वोधन मे कार्यशाला के उद्देश्यों के ऊपर प्रकाश डालते हुए कहा कि REDD + संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के तहत वनों की कटाई और वनों के क्षरण, वनों के संरक्षण, वनों के सतत प्रबंधन और वनों में वन कार्बन स्टॉक को बढ़ाने के लिए वानिकी क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन शमन विकल्पों में से एक है। REDD+ के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का उपयोग करने के लिए, विकासशील देशों को राष्ट्रीय REDD+ रणनीति, वन संदर्भ उत्सर्जन स्तर / वन संदर्भ स्तर, राष्ट्रीय वन निगरानी प्रणाली और सुरक्षा उपायों की सूचना प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। भारत ने अपनी राष्ट्रीय REDD+ रणनीति और वन संदर्भ स्तर विकसित किया है और UNFCCC को प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय वन निगरानी प्रणाली (National Forest Monitoring System) और रक्षोपाय सूचना प्रणाली (Safeguards Information System) का विकास प्रक्रियाधीन है। उपरोक्त पर चर्चा करके आवश्यक सुधार हेतु सुझाव प्राप्त किया जाना ही कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है जिससे कि कार्यक्रम अधिक-अधिक व्यावहारिक रुप से विकसित किया जा सके।

श्री अरुण सिंह रावत, IFS, महानिदेशक, ICFRE देहरादून ने बताया कि भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) ने भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय REDD+ रणनीति विकसित की है। अब ICFRE हितधारक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से REDD+ के लिए सुरक्षा उपाय सूचना प्रणाली (SIS) में हितधारकों से चर्चा कर के सुझाये गये आवश्यक सुधारों को शामिल करने की प्रक्रिया में है। REDD+ कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों को एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में पहचाना गया है। ICFRE ने वन विभाग, राज्य सरकार के अन्य लाइन विभागों, अनुसंधान और अकादमिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों से संबंधित वन सुरक्षा समिति (JFM) समिति के सदस्य, किसान और स्थानीय समुदाय के सदस्य आदि हितधारकों के बहुमूल्य इनपुट / सुझाव / टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राफ्ट सुरक्षा उपायों पर हितधारक परामर्श किये जाने की योजना बनाई है तथा उसी के अंतर्गत इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है।

श्री वी आर एस रावत (विशेषज्ञ REDD+) ने REDD + और भारत के REDD + सुरक्षा उपायों के दृष्टिकोण पर एवं डॉ. आर.एस. रावत, वैज्ञानिक, आईसीएफआरई देहरादून ने REDD+ के लिए सुरक्षा उपायों, सूचना प्रणाली पर हितधारकों के परामर्श पर अपनी विस्तृत प्रस्तुति दी।

कार्यशाला मे श्री रविकांत सिन्हा, IFS, PCCF और वन बल प्रमुख, पश्चिम बंगाल, डॉ .जोस टी .मैथ्यूज, IFS, PCCF (RMD), पश्चिम बंगाल, श्री ए.के. पांडे, आईएफएस, पीसीसीएफ और वन बल प्रमुख, बिहार, के प्रतिनिधि श्री पी.के. वर्मा, IFS, PCCF और वन बल प्रमुख, झारखंड, के प्रतिनिधि श्री सुब्रत महापात्रा, IFS, डीडीजी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (केंद्रीय), श्री अनुराग भारद्वाज, आईएफएस, एडीजी, आईसीएफआरई, देहरादून डॉ. संजय श्रीवास्तव, IFS, APCCF, CAMPA, झारखंड, डॉ .कैलाश चंद्र, निदेशक, ZSI, कोलकाता, डॉ. श्रीमती(एस .दुबे, IFS, APCCF (Res & Mon), पश्चिम बंगाल, डॉ .शरद तिवारी, श्री संजीव कुमार, वैज्ञानिक, डॉ. शम्भूनाथ मिश्रा, मुख्य तकनीकी अधिकारी व.उ.स., रांची, श्री टी.महतो, श्री सरोज महापात्र, प्रदान, डॉ. (प्रोफेसर) प्रसेंजित मुखर्जी, श्री शरद सिंह, श्री नइम अंसारी, प्रगतिशील किसान के अलावा मुख्यतः कॉलेजों के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालयों, केंद्रीय एवं राज्य वन मंत्रालय के सदस्यों, गैर सरकारी संगठन जैसे प्रदान, औद्योगिक क्षेत्र के गणमान्य अतिथि ने भाग लिया .डॉ .योगेश्वर मिश्र ने कार्यक्रम के अंत मे सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन किया।

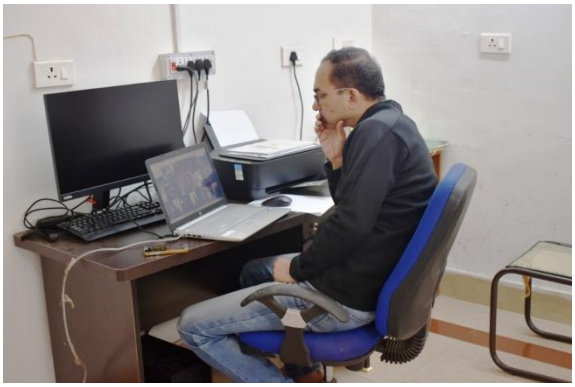

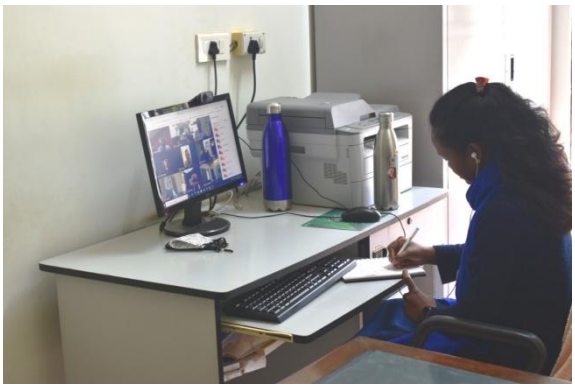

REDD+ कार्यशाला की झलकियां